(c) whether any report has been obtained from the State Government in this regard; and

(d) if so, the details therof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (CHANDRADEO PRASAD VARMA): (a) During the current year no such proposal has been received.

(b) to (d) Question does not arise.

Non-completion of Saurashtra Wells by Essar Limited

146. SHRI ASHOK MITRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item carried by Indian Express on October 29, 1996 that Oil India Limited entered into a contract with a Mumbai-based company Essar Limited for turn-key drilling of three wells in Saurashtra and one well in the Mahnadi Basin;

(b) whether it is a fact that despite advance payment of rupees 70 crores, the company has failed to fulfil the stipulations for completing the three Saurashtra wells; and

(c) what arrangements Oil India Limited is contemplating to recover the money?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) **Yes,** Sir. The news item appeared in the Telegraph dated 29.10.96.

(b) and (c) The payments made by Oil India Ltd. in respect of mobilisation charges and part of the jobs completed for the three Saurashtra wells is Rs. 52.92 crores and no advance payment of Rs. 70 crores has been made to the contractor. The contract has been terminated on 12.10.96 and performance guarantee invoked. However, the contractor has obtained an injunction from the Court and the decision of the Court is awaited.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित करने के प्रस्ताव

147. श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) सरकार द्वारा कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है;

(ग) किन-किन राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इनमें किस-किस प्रकार के उद्योग स्थापित किए जाने हैं; और

(घ) इसके परिणाम स्वरूप कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय): (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों (93-94, 94-95 और 95-96) के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कुल 1,555 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन पेश किए गए जिनमें अधिकांश को खाद्य उत्पादों के लिए औद्योगिक लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह इसी अवधि के दौरान सरकार ने संयुक्त उद्यम, शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों और विदेशी सहयोग के लिए 612 प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया। इन औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों और अनुमोदनों से 3.71 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

अनाज और अनाज आधारित उत्पादों, फल तथा सब्जी उत्पादों, दूध तथा दूध उत्पादों, मछली प्रसंस्करण और एक्वाकल्चर, उपभोक्ता उद्योग, मांस तथा मांस उत्पाद आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना संबंधी प्रस्ताव अधिकांश राज्यों से प्राप्त हुए हैं।

Fast Track Power Projects in Andhra Pradesh

148. DR. MOHAN BABU: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the present status of the three fast track power projects in Andhra Pradesh at Jegurupadu, Kakinada and Visakhapatnam;

(b) the target for completion of the projects; and

(c) the action proposed to be taken to persuade for timely completion of the projects by private investors?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) Jegurupadu TPS (216 MW) of M/s GVK Industries and